IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कर्पूरी ठाकुर का समाजवादी आंदोलन में भूमिका

स्मिता कुमारी

शोध छात्रा, इतिहास विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

सारांश:

बिहार की विवादास्पद राजनीति से निपटने के लिए उनके अद्वितीय कौशल और क्षमता के बावजूद कर्पूरी ठाकुर की जाति पृष्ठभूमि ने हमेशा उनके नेतृत्व को छायांकित किया। कर्पूरी ठाकुर के जीवनकाल के दौरान और बाद में जिन सवालों पर बहस होती रही, वे बिहार में पिछड़ी जाति की राजनीति को मज़बूत करके कांग्रेस विरोधी राजनीति की नींव को आकार देने में उनके प्रभाव के इर्द-गिर्द घूमते रहे। उन्होंने मध्यस्थ जातियों की राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया और राज्य में उच्च जाति / वर्ग की राजनीति के लिए एक विकट चुनौती पेश की। कर्पूरी राज्य के प्रमुख समाजवादी नेताओं में से एक थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय के विचार को गति प्रदान की और पिछड़ी जाति की राजनीति की रूपरेखा को प्रभावित किया, जिसने 1967 की शुरुआत में अपनी पहली चुनावी जीत का प्रदर्शन किया और 1990 के बाद से राज्य की राजनीति पर हावी है। नाई (नाई) जाति से संबंधित एक परिवार जो बिहार की आबादी का 1.5% से भी कम है, ठाकुर 1960 से 1987 के बीच बिहार में समाजवादी पार्टी और पिछड़ी जाति की राजनीति के केंद्र चरण पर कब्जा करने में कामयाब रहे। उस समय के अन्य समाजवादी नेताओं के समान राजनीति में उनकी दीक्षा स्वतंत्रता आंदोलन में संलग्नता के साथ शुरू हुई, लेकिन उनके वैचारिक जुड़ाव ने उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी की ओर रुख किया। 1960 के दशक के दौरान, वह मध्यवर्ती (पिछड़ी पढ़ें) जातियों की राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि के रूप में उभरे और इस प्रकार कांग्रेस (आई), कांग्रेस (ओ) और जनसंघ जैसे राजनीतिक दलों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की मुख्य रूप से उच्च जाति के नेताओं का वर्चस्व है। 'लोहियावादी' राजनीतिक परंपरा से प्रभावित और सामाजिक रूप से, ठाकुर ने बिहार में राजनीति की प्रमुख अवधारणा और कल्पना को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू किया।

परिचय:

हालांकि 1990 के दशक के बाद जाति-आधारित लामबंदी और अन्य पिछड़ी जातियों के पक्ष में इसके वृहद निहितार्थों की अभूतपूर्व सफलता अधिक स्पष्ट हो गई, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रगति ने विविध प्रक्षेपवक्र हासिल कर लिए। बिहार में, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कुछ नेताओं ने पिछड़ी जाति की राजनीति के सामाजिक-राजनीतिक रूपरेखा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो दशकों से फली-फूली और अंततः 1990 के दशक से शासकीय राजनीति के रूप में उभरी। पिछड़ी जाति की राजनीति के अपने आकलन में, जाफरलॉट2 इस तथ्य को रेखांकित करता है कि बिहार एक समाजवादी प्रयोगशाला रहा है, जहां कांग्रेस के प्रभुत्व के शुरुआती दौर में भी समाजवादी पार्टियों ने मिलकर 20 से 25% वोट हासिल किए थे। समाजवादी पक्ष में, कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी के दावे में एक प्रमुख भूमिका निभाई, और उनकी गतिविधियों ने कांग्रेस की कीमत पर एसएसपी के उदय की व्याख्या की। 3 कर्पूरी की राजनीति राजनीतिक के लिए पिछड़ी जाति समूहों के बीच एक गठबंधन बनाने की दिशा में एक गंभीर प्रयास थी। मान्यता और दावा। हालाँकि, इस प्रयास को कई जटिलताओं और बाधाओं का सामना करना पड़ा। पिछड़ी जाति के नेताओं की व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं, वास्तविक राजनीति के दायित्वों और माँगों, विभिन्न नेताओं के करियर की संभावनाओं और उनकी वैचारिक प्रतिबद्धताओं ने उनके लिए मतभेदों को दूर करना बहुत कठिन बना दिया। इस भेदभाव ने विविध निम्न जाति समूहों को अलग रखा, और वे आर्थिक या वैचारिक कारकों के आधार पर एक स्थिर और विश्वसनीय राजनीतिक गठबंधन बनाने में असमर्थ रहे। रॉय बताते हैं कि शूद्र जातियों के बीच भय, अविश्वास और भेदभाव उनके राजनीतिक गठबंधन को रोकते हैं और उनके राजनीतिक प्रभुत्व को रोकते हैं। राम मनोहर लोहिया की राजनीति से प्रभावित, बाधाओं के खिलाफ, कर्पूरी ठाकुर बिहार में समाजवादी राजनीति के एक युवा और प्रेरक चेहरे के रूप में उभरे। लोहिया की समाजवादी राजनीतिक परंपरा और निचली जाति के आंदोलनों के बीच संबंधों के बारे में प्रभावी अभिव्यक्ति, "सामाजिक न्याय और अनुष्ठानिक भेदभाव के मुद्दों पर निचली जातियों की क्षैतिज लामबंदी की राजनीतिक क्षमता" को पहचानना कर्पूरी की राजनीति का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। ठाकुर की चुनावी सफलता अनुकरणीय रही है, और उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर 1952 से लड़े सभी चुनावों में जीत हासिल की। विभिन्न मुद्दों और समाज के वंचित वर्ग की चिंताओं पर विधान सभा के भीतर उनका उग्र और तर्कपूर्ण योगदान समाज और राजनीति के हाशिये पर लोगों और समुदायों के साथ उनके सीधे जुड़ाव से मेल खाता था। सामाजिक न्याय की अवधारणा, जन-केंद्रित विकास का विचार और इसके इर्द-गिर्द जन लामबन्दी का विचार उनके विचारों के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। उन विचारों और समझ ने उनके अधिकांश राजनीतिक कार्यों की जानकारी दी। यह पेपर सामाजिक न्याय, लोकप्रिय राजनीति और सबाल्टर्न समूहों के दावे के बारे में कर्पूरी ठाकुर के विचारों और अभिव्यक्ति की जांच करता है। ठाकुर लोकप्रिय आंदोलनों के माध्यम से सामूहिक लामबंदी और मुखरता के अग्रदूत थे, और उनकी रणनीतियों ने बिहार में अब तक बहिष्कृत और हाशिए की जातियों और समुदायों की शक्ति का प्रदर्शन किया।

अध्ययन का विश्लेषण:

कर्पूरी की विवादास्पद राजनीति और लोकप्रिय आंदोलनों में उनके योगदान को समझने के लिए, अखबार अतीत के कुछ पहलुओं की पड़ताल करेगा:- 1) समकालीन सहयोगियों के साथ उनका जुड़ाव और मुकाबला क्या था? 2) समाजवाद और पिछड़ी जातियों और समुदायों के लिए इसके निहितार्थ की उनकी अभिव्यक्ति क्या थी जिसने उन्हें बिहार में प्रतिस्पर्धी समाजवादी राजनीति के केंद्र-मंच पर कब्जा करने में मदद की? 3) राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे के साथ उनके वैचारिक संरेखण और विवाद के बिंदुओं

को हम कैसे समझते हैं? 4) लोकप्रिय राजनीति के रूप में किसानों, किसानों और छात्रों की राजनीति और आंदोलन के मुद्दों से वह कैसे जुड़े? 5) आक्रामक राजनीति/लोकप्रिय आंदोलनों के माध्यम से शहरी परिवेश में छात्रों, किसानों और पिछड़ी जातियों के बीच विषय-पद्धति/राजनीतिक विषय और नागरिकता के उद्भव की उभरती अवधारणा को कैसे स्थापित किया जा सकता है? 6) एक मुखर विपक्षी नेता और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके विधायी कार्यों को कोई कैसे समझ सकता है? 7) प्रभुत्वशाली सामाजिक ढाँचे ने उसके 'विवादास्पद' निर्णयों से कैसे निपटा? 8) कर्पूरी की राजनीति को चरमपंथियों के गठजोड़ और व्यावहारिकता की राजनीति से कैसे समझा जा सकता है? और अंत में, 9) 'कर्पूरी फॉर्मूले', 'कर्पूरी विभाजन' और इसके पीछे लोकप्रिय राजनीति के तत्वों के पीछे की राजनीतिक रणनीतियों को कोई कैसे समझता है?

कर्पूरी ठाकुर की राजनीति को समझने के लिए, देश में समाजवादी ब्लॉक के भीतर नेतृत्व संघर्ष को समझने की जरूरत है। समाजवादी नेताओं के बीच विखंडन की व्याख्या करते हुए, फिकेट ने 1972 में लिखा, "महान समाजवादी नेता- जयप्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया, जे.बी. कृपलानी, और अशोक मेहता- सभी प्रथम दाता होने की प्रवृत्ति रखते थे, प्रत्येक अपनी तरह की राजनीतिक मुक्ति की वकालत करते थे, प्रत्येक फलहीन वैचारिक अमूर्तता में लिप्त होना भारतीय बौद्धिक राजनेताओं की विशेषता है और प्रत्येक दूसरों के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। नतीजतन, समय के साथ, इन सभी नेताओं ने पार्टी का त्याग कर दिया, दलबदल कर दिया, या पार्टी से निष्कासित कर दिया, हर बार अपने वफादार समर्थकों को अपने साथ ले कर पार्टी को थोड़ा कमजोर छोड़ दिया।'5 बिहार में, अधिकांश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (▯▯▯) कैडर लंबे समय से कांग्रेस में लगातार लहरों में चले गए थे - 1964 में अशोक मेहता ने अपने समर्थकों के साथ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दी, अपने साथ अनुमानित एक-तिहाई ▯▯▯ कैडर ले गए। बिहार में दलबदल ने, एक तरह से पिछड़ी जाति के नेताओं के लिए अधिक जगह बनाई क्योंकि कई उच्च जाति के समाजवादी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वास्तव में, 1957 में लोहिया की समाजवादी पार्टी के साथ बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग संघ के विलय और 1959 में लोहिया के समर्थकों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 60 प्रतिशत आरक्षण हासिल करने के प्रस्ताव को अपनाने के बाद से, और संगठनों और सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यक समाजवादी राजनीति का मुख्य एजेंडा बन गए। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की योजना ने एक तरह से समाजवादियों के दो गुटों के बीच अंतर को चौड़ा कर दिया: संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (▯▯▯) और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (▯▯▯) पीएसपी)। इसने बड़ी संख्या में उच्च जाति के समाजवादी नेताओं को भी अलग-थलग कर दिया। इन उच्च जाति के नेताओं में प्रतिबंधित राजनीतिक संभावनाओं की भावना प्रबल थी, जिन्हें बाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा सहयोजित कर लिया गया था। एसएसपी ने इन समूहों के लिए 60% आरक्षण पर जोर दिया; इस पर पीएसपी का रवैया काफी नरम रहा। इसके अलावा, केंद्रीय समाजवादी नेताओं के बीच व्यक्तित्वों के टकराव और नेताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का समाजवादी राजनीति के विखंडन और पुनर्निर्माण में निहितार्थ था। एसएसपी के अधिक जमीनी नेतृत्व के विपरीत, पीएसपी पार्टी का अभिजात वर्ग ज्यादातर उच्च जाति, शिक्षित और बड़े पैमाने पर शहरीकृत था। फिकेट7 ने कहा कि अन्य ऐतिहासिक और वैचारिक विचारों के साथ-साथ नेताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण, पीएसपी ने केवल अनिच्छा से भारतीय समाज में वंचित समूहों (पिछड़ी जातियों, जनजातियों, महिलाओं) के लिए प्रतिनिधित्व की पूर्व निर्धारित डिग्री की मांग का जवाब दिया। संदर्भ ने कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं द्वारा समर्थित राजनीति के लिए एक बेहतर स्थान और गुंजाइश की पेशकश की।

वे "संसोपा ने बंधी गाँठ, पीछे पवेन सौ में साथ" (संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी पिछड़ों के लिए 60 प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित) के नारे के प्रबल समर्थकों में से एक बन गए और उसी के लिए प्रमुख प्रचारक बन गए। अन्य लोकप्रिय नारे, जैसे "लोहिया-कर्पूरी की लालकार, बदलो-बदलो ये सरकार" (लोहिया-कर्पूरी ने राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया है) और "सौ से कम न हज़ार से ज्यादा, समाज का यही तकजा" (न सौ से कम न हजार से अधिक, यही समाजवादी विचारधारा है) ने समाज के पिछड़े और दलित वर्गों की कल्पना को पकड़ा।

इसके अलावा, भाषा के सवाल ने भी समाजवादियों को अलग रखा। एसएसपी ने अपने उत्तर भारतीय आधार को दर्शाते हुए, हिंदी भाषा की बिना शर्त स्वीकृति के पक्ष में बहुत कड़ा रुख अपनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा होने पर सहमत होते हुए, पीएसपी ने देश के अनिच्छुक क्षेत्रों पर हिंदी को थोपने का विरोध किया। समाजवादी राजनीति के साथ दुर्दशा पर विस्तार से बताते हुए, ब्रास9 ने तर्क दिया कि समाजवादी विभाजन राजनीति में सत्ता, व्यक्तिगत हित और सिद्धांतों के जटिल अंतर्संबंध को प्रदर्शित करता है। जून 1964 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (□□□) में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (□□□) और सोशलिस्ट पार्टी (□□) के विलय के बाद नेताओं के एक वर्ग का दलबदल, लोहिया के नेतृत्व का सवाल और जनसंघ के साथ गठबंधन का मुद्दा और सीपीआई पर जोरदार बहस हुई और पार्टी के भीतर चुनाव लड़ा गया। गठबंधनों के इर्द-गिर्द बहस, संवाद और गलतफहमी का लोकप्रिय राजनीति और आंदोलनों को आकार देने के साथ-साथ नेतृत्व के सवाल पर भी प्रभाव पड़ा है। 1960 के दशक के अंत/1970 के दशक के प्रारंभ में सरकार बनाने के लिए एसएसपी, जनसंघ, कांग्रेस (ओ) और स्वतंत्र पार्टी का गठबंधन समाजवादी राजनीति में गंभीर विवाद की विशेषता बना रहा। इस पृष्ठभूमि में कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं की भूमिका, प्रासंगिकता और रणनीति की जांच की जाती है।

1965 और 1972 के बीच, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, और भोला प्रसाद सिंह बिहार में एसएसपी के प्रमुख दल थे, लेकिन वे गठबंधन के सवालों और मुद्दों पर मतभेद रखते थे। "जिस विंग के लिए भोला प्रसाद सिंह प्रवक्ता थे, उन्होंने कांग्रेस (आर) के खिलाफ कांग्रेस (ओ), जनसंघ और स्वतंत्र के साथ गठबंधन के लिए तर्क दिया, जबकि रामानंद तिवारी के नेतृत्व वाले विंग ने कांग्रेस (आर) और पीएसपी के साथ गठबंधन का समर्थन किया। इस समय कर्पूरी ठाकुर की किसी भी पक्ष के साथ दृढ़ता से पहचान नहीं थी□ (ब्रास 1976:31)। 1969-1971 के दौरान गठबंधन की रचना के पेचीदा मुद्दे के आसपास दो समाजवादी दिग्गजों, रामानंद तिवारी और कर्पूरी ठाकुर के बीच सामान्य सौहार्द और एक साथ आंतरिक प्रतिद्वंद्विता राजनीतिक परिदृश्य पर हावी रही। जहां एसएसपी, कांग्रेस (ओ), जनसंघ का एक समूह रामानंद तिवारी को सीएम उम्मीदवार के समर्थन में आया, वहीं दूसरे समूह ने ठाकुर की उम्मीदवारी का प्रचार किया। उच्च जाति के नेता को सीएम के रूप में स्वीकार करने की आशंका और दक्षिणपंथी जनसंघ के साथ गठबंधन के जोखिम को पिछड़े वर्ग के हितों और समाजवादी विचारधारा के साथ विश्वासघात माना गया। इन विचार-विमर्शों और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों को कर्पूरी की साजिश माना गया। एक नेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता की कमी के बारे में पता चलने के बाद, रामानंद तिवारी ने एसएसपी के आंतरिक विवाद के बारे में खुलकर बात की और जनसंघ के खिलाफ मुखर रूप से लिखा। 28 फरवरी 1970 को एसएसपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में तिवारी ने रेखांकित किया कि जनसंघ का इरादा देश को हिंदू फासीवाद की ओर धकेलना है। उन्होंने लिखा, □जनसंघ की नींव साम्प्रदायिक तनाव और नफरत है। एसएसपी के लिए जेएस के साथ सरकार बनाना अस्वीकार्य है... हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सरकार बनाना केवल साधन है, अंत नहीं। ऐसा लगता है कि हम इसे अंत मानने लगे हैं।'10 कांग्रेस पार्टी ने एसएसपी में आंतरिक प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया और वह

दारोगा प्रसाद रॉय के नेतृत्व वाली सरकार को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही; हालाँकि, सरकार मुश्किल से नौ महीने ही चल सकी। विडंबना यह है कि दिसंबर 1970 में, कर्पूरी ठाकुर ने जनसंघ के समर्थन से सरकार बनाई और रामानंद तिवारी उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों में से एक बने। वास्तव में, गठबंधन के आसपास की आशंका, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की जातिगत पहचान, एक उच्च जाति के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने का विरोध और एसएसपी में विभाजन के डर ने एक समझौते पर काम किया जिसने कर्पूरी ठाकुर को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। सरकार एसएसपी, कांग्रेस (ओ), जनसंघ, स्वतंत्र और अन्य छोटी पार्टियों का गठबंधन थी। राजनीतिक विकास ने जनसंघ को शासन में भागीदारी के लिए स्थान प्रदान किया, एक अवसर जिसे पार्टी आने वाले वर्षों और दशकों में मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकृति को व्यापक बनाने में चतुराई से उपयोग कर सकती थी।

राजनीतिक विकास ने ठाकुर के राजनीतिक शिल्प और कौशल को प्रदर्शित किया जिससे वह खुद को समाजवादी ब्लॉक के सबसे प्रमुख नेता के रूप में स्थापित कर सके। राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के आरोपों के बावजूद, कर्पूरी ठाकुर पार्टी के विभिन्न गुटों द्वारा सबसे स्वीकार्य नेता के रूप में उभरे। ब्रास11 को यह दिलचस्प लगा कि "केंद्र और राज्य स्तर पर अधिकांश विवादों में, कर्पूरी ठाकुर ने खुद को कास्ट किया और अन्य लोगों द्वारा एक प्रमुख नायक के बजाय मध्यस्थ और शांतिदूत की भूमिका में डाला गया"। घटनाओं का क्रम, पर्दे के पीछे की राजनीतिक रणनीति और उसके नीतिगत नतीजों ने आने वाले दशकों में बिहार की राजनीति का भविष्य तय किया। कर्पूरी ठाकुर द्वारा सरकार के गठन के बाद अपनाई गई नीतियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य में पिछड़े वर्ग के नेताओं का राजनीतिक पुनरुत्थान जारी रहेगा, कम से कम गैर-कांग्रेसी दलों के भीतर। पार्टी के भीतर गुटबाजी के इन चरणों के माध्यम से नेविगेट और बातचीत, समाजवादी नेताओं के बीच एक-अपमान और लोकप्रिय आंदोलनों की मांगें, कर्पूरी विभिन्न गुटों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते रहे और विपक्षी ब्लॉक में सबसे स्वीकार्य नेता के रूप में सामने आए। उन्होंने राज्य में पार्टी के भीतर और राष्ट्रीय राजनीति में भी आंतरिक कलह के दौरान चुप्पी, तटस्थता और अस्पष्टता को रणनीति के रूप में नियोजित किया।

मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के अगले दिन, ठाकुर के मंत्रिमंडल ने राजभाषा अधिनियम को सख्ती से लागू करने का पहला बड़ा निर्णय लिया और सभी आधिकारिक संचार के लिए हिंदी का उपयोग अनिवार्य कर दिया। □जनता की भाषा का आधार, लोकतंत्र का आधार□ शीर्षक के साथ अखबार के संपादकीय में कहा गया है, □मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने प्रेस को सूचित किया है कि उन सभी की सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी का उल्लेख किया जाएगा। कौन इस निर्देश का उल्लंघन करेगा ... यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के उपयोग के कारण बिहार के आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा ... अंग्रेजी द्वारा संरक्षित सरकार और लोगों के बीच की खाई लोगों को यह अनुभव नहीं होने दे रही है कि वे एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं □।12

"अंगरेजी में अब काम ना होगा, फिर से देश गुलाम न होगा" (हम अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे, हम देश को फिर से उपनिवेश नहीं होने देंगे) और "राष्ट्रपति का बेटा या चपरासी की संतान; भंगी या भवन हो, सबकी शिक्षा एक समान□ (राष्ट्रपति का बच्चा या चपरासी का बच्चा, सफाई कर्मचारी या ब्राह्मण, सभी को समान शिक्षा मिलेगी) ने सरकारी नीति में अपनी प्रतिध्वनि प्राप्त की। इससे पहले, शिक्षा विभाग के साथ उपमुख्यमंत्री के रूप में, कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया था और इसे हाई स्कूल में छात्रों के लिए एक वैकल्पिक पेपर बना दिया था। उनके लिए यह स्पष्ट था कि पिछड़े समुदायों और

IJCRT

ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे अक्सर अंग्रेजी के अनिवार्य विषय के कारण परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते थे। चूंकि छात्र मैट्रिक में अर्हता प्राप्त नहीं कर सके, छात्र उच्च शिक्षा के लिए पात्र नहीं थे और इसलिए रोजगार के अवसरों से वंचित रह गए। जिन छात्रों ने इस चरण के दौरान अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा पूरी कर ली थी, उन्हें अक्सर तिरस्कारपूर्वक "कर्पूरी डिवीजन" के रूप में संदर्भित किया जाता था। कृपालु उच्च जाति और समाज के एक प्रभावशाली वर्ग ने ठाकुर पर शिक्षा व्यवस्था में अराजकता लाने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री के रूप में, उन्होंने 3.5 एकड़ सिंचित और 7 एकड़ असिंचित भूमि वाले लोगों से राजस्व (मालगुजारी) का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया। नीति की घोषणा लोहिया के नारे "जिस खेत से लाभ नहीं, हमें पर लगे लगन नहीं" के अनुरूप थी। इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को काफी राहत मिली है। इसने स्पष्ट रूप से सरकार के गतिशील समाजवादी चरित्र को प्रदर्शित किया। इन प्रगतिशील घोषणाओं ने इस आशंका को कम कर दिया कि दक्षिणपंथी जनसंघ समर्थित गठबंधन सरकार गरीब-समर्थक समाजवादी विचारधाराओं और एजेंडे से समझौता करेगी।

पिछड़ी जाति के मतदाताओं को मजबूत करने के लिए, एसएसपी ने गैर-अभिजात्य समूहों से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को नामांकित किया, और समाजवादियों ने बड़ी संख्या में ओबीसी विधान सभा सदस्यों (विधायकों) को चुना; 1967 के चुनावों में, एसएसपी के लगभग 40 प्रतिशत विधायक बिहार में निचली जाति से आए थे।13 समाजवादी पार्टी के जटिल राजनीतिक क्षेत्र में अपनी क्षमता के साथ और राज्य पार्टी इकाई पर अपनी पकड़ स्थापित करने के बाद, कर्पूरी ठाकुर बन गए 1960 के दशक में लोकप्रिय राजनीति और जन आंदोलनों में अधिक आक्रामक और मुखर। 1965 में, उन्होंने 'जन-विरोधी' और 'छात्र-विरोधी' नीतियों और कांग्रेस सरकार के दमनकारी अधिनियम के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन का नेतृत्व किया, जो बड़े पैमाने पर जन समर्थन जुटा सकता था। व्याकुल राज्य ने हिंसा और विपक्ष की आवाजों को दबाने का सहारा लिया; ठाकुर और रामानंद तिवारी जैसे प्रमुख नेताओं पर लाठीचार्ज की घटना सत्तारूढ़ शासन के लिए एक असाधारण विवादास्पद मुद्दा बन गई। जमशेदपुर में टाटा कंपनी द्वारा संचालित उद्योगों में कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके विरोध के दौरान लोगों के कारण और लोकप्रिय राजनीति पर विश्वास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण सामने आया। कार्यकर्ताओं के समर्थन में उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया जो 28 दिनों तक चला। नतीजतन, प्रबंधन श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, साप्ताहिक अवकाश और नौकरी की सुरक्षा बढ़ाने पर सहमत हो गया।

निष्कर्ष

1940 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक चार दशकों तक फैली कर्पूरी की गतिशील राजनीति ने समाज के निचले तबके को जगाने में उनके आविष्कारशील दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। रणनीतियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण बिहार में जाति और वर्ग जागरूकता की झलक लाने के इर्द-गिर्द घूमती थीं जो सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित जाति समूहों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को रोक रही थी। वास्तव में, तर्क, अभिव्यक्ति और एजेंडा-सेटिंग से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्पूरी की राजनीति सरकार के आचरण से सूचित और प्रभावित थी और प्रयास हमेशा इन आचरणों को मनाने का था। उन्होंने न केवल नीति/विधायी विचार-विमर्श में मुखर जुड़ाव के माध्यम से बल्कि विपक्षी मांगों और कार्य योजना के माध्यम से भी सरकारी आचरण को प्रभावित करने की कोशिश की। सरकारी ढांचे के भीतर खुद को स्थापित करते हुए, कर्पूरी ने सरकारी तर्कसंगतता को नियोजित किया ताकि सबाल्टर्न आबादी की स्थिति को आगे बढ़ाया जा सके। अक्सर उन्होंने सरकार के उद्देश्य को परिभाषित किया और सरकारी भूल-चूक की सीमाओं और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उनकी अधिकांश

राजनीतिक अभिव्यक्ति और रणनीतियों में, लोकतंत्र के खिलाफ राज्य को रेखांकित करने की प्रवृत्ति स्पष्ट थी। हालाँकि, शासन करने के साथ-साथ विरोध करने के उनके दृष्टिकोण में, जनसंख्या गणना पर जोर, राजनीतिक अंकगणित और बहिष्कृत आबादी की देखभाल और कल्याण के नाम पर तर्कसंगतता हमेशा स्पष्ट थी। मिचेल डीन41 ने जोर देकर कहा कि गणना केंद्रीय है क्योंकि सरकार की आवश्यकता है कि "सही तरीके" को परिभाषित किया जाए, विशिष्ट "अंतिमताओं" को प्राथमिकता दी जाए, और एक इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए अंततः रणनीति तैयार की जाए।

संदर्भ:

अरुण सिन्हा, "जनता एक नेता का चुनाव करती है", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम। 12, नहीं। 26 (जून. 25, 1977), पृ. 1001.

2 क्रिस्टोफ जैफ्रेलॉट, इंडियाज साइलेंट रेवोल्यूशन: द राइज ऑफ द लो कास्ट्स इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स। नई दिल्ली: परमानेंट ब्लैक, 2003।

3 जेफ्रेलॉट, इंडियाज साइलेंट रेवोल्यूशन, पृ. 266.

4 रामाश्रय रॉय, "बिहार में स्ट्रक्चरल रिगिडिटी, सोशल मोबिलाइजेशन एंड पॉलिटिकल "इमोबिलाइज"। इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वॉल्यूम। 49, नहीं। 1 (जनवरी - मार्च 1988), पृष्ठ 62।

5 लुईस पी. फिकेट, (जूनियर) "द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया -- 1952-1972: एक अंतिम आकलन"। एशियाई सर्वेक्षण, वॉल्यूम। 13, नहीं। 9 (सितंबर, 1973), पृष्ठ 829।

6 एफ. फ्रैंकल, "डिक्लाइन ऑफ ए सोशल ऑर्डर", एफ. फ्रैंकल एंड एम.एस.ए. राव (एड्स.), डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन इंडिया (खंड 2) में। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1989।

7 फिकेट, (जूनियर) "द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया", पृष्ठ 831।

8 फिकेट, (जूनियर) "द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया", पृष्ठ 831।

9 पॉल आर. ब्रास, "नेतृत्व संघर्ष और भारतीय समाजवादी आंदोलन का विघटन: व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, शक्ति और नीति"। कॉमनवेल्थ और तुलनात्मक राजनीति का जर्नल। खंड। 14, नहीं। 1. (1976) पृ.21।

10 हिन्दी दैनिक आर्यावर्त में 12 मार्च 1970 को प्रकाशित पत्र।

11 ब्रास, "नेतृत्व संघर्ष और भारतीय समाजवादी आंदोलन का विघटन", पृष्ठ 32।

12 आर्यावर्त, 25 दिसम्बर 1970।

13 क्रिस्टोफ़ जाफ़रलॉट, "हिंदी बेल्ट में अन्य पिछड़े वर्गों का उदय"। द जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज, वॉल्यूम। 59, संख्या 1. (2000) पीपी. 86-108.

14 जॉन आर. वुड, "एक्स्ट्रा-पार्लियामेंटरी ऑपोजिशन इन इंडिया: एन एनालिसिस ऑफ पॉपुलिस्ट एजिटेशंस इन गुजरात एंड बिहार"। प्रशांत मामले, वॉल्यूम। 48, नहीं। 3 (शरद ऋतु, 1975), पृष्ठ 315।